

#### असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 835] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 2019/फाल्गुन 3, 1940 No. 835] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2019/PHALGUNA 3, 1940

# श्रम और रोजगार मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2019

का.आ. 966(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची में मद 32 के अधीन आने वाली 'बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक' में सेवा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित की जाए।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त उद्योग को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2016-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजिसंहोत, संयुक्त सचिव

1192 GI/2019 (1)

#### MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2019.

**S.O. 966(E).**— Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Bank Note Paper Mill India Private Limited, Mysore, Karnataka which is covered by item 32 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares from the date of publication of this notification that the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/1/2016-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.